कार्बन उत्सर्जन पर कीमत लगाने का समय

चर्चा में क्यों?

- एक कार्बन टैक्स, डीकार्बोनाइजेशन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

भारत द्वारा उठाये जाने वाले कदम

- भारत सहित अन्य देशों में, राजकोषीय नीति में कार्बन टैक्स को लागू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को निर्धारित करने की बात कही गयी है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष(IMF) ने संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत के लिए क्रमशः $75, $50, और $25 प्रति टन कार्बन की न्यूनतम कीमत को प्रस्तावित किया है। इससे 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन में 23% की कमी लाने की उम्मीद की जा रही है।
- भारत की 'कम उत्सर्जन' प्रणाली की दीर्घकालिक रणनीति में परमाणु ऊर्जा और इथेनॉल शामिल हैं।
- वायु और वन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के माध्यम से पर्यावरणीय हानि के साथ जीडीपी विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप कार्बन का निरंतर उत्सर्जन को रहा है।
- भारत G-20 के अध्यक्ष के रूप में कार्बन मूल्य निर्धारण में अग्रणी भूमिका निभा सकता है, जो डीकार्बोनाइजेशन के अप्रत्याशित रास्ते खोलेगा।

मूल्य निर्धारण के प्रकार

कार्बन के मूल्य निर्धारण के 3 प्रकार हैं:

- कोरिया और सिंगापुर की तरह घरेलू स्तर पर कार्बन टैक्स की स्थापना;
- यूरोपीय संघ (EU) और चीन की तरह उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) का उपयोग;
- कार्बन सामग्री पर आयात शुल्क लागू करना, जैसा कि यूरोपीय संघ प्रस्तावित कर रहा है।
- 46 देशों द्वारा वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन का केवल 30% कवर किया जाता है और केवल 6 डॉलर प्रति टन कार्बन की औसत कीमत पर, प्रदूषण से अनुमानित क्षति का एक अंश प्रदान किया जाता है।

उपाय

- मूल्य निर्धारण के तीन तरीकों में से, भारत को कार्बन टैक्स अधिक उपयुक्त लग सकता है क्योंकि यह जीवाश्म ईंधन को सीधे तौर पर हतोत्साहित कर सकता है, जबकि राजस्व में वृद्धि कर सकता है जिसे ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों में निवेश किया जा सकता है या कमजोर उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- यह पेट्रोलियम करों की अधिक अक्षम योजना को प्रतिस्थापित कर सकता है जो सीधे उत्सर्जन के उद्देश्य से सम्बद्ध नहीं हैं।
- वैसे, सऊदी अरब और रूस गैसोलीन की कीमतों (करों और सब्सिडी सहित) के निचले सिरे पर हैं, मध्य श्रेणी में चीन और भारत, और उच्च अंत में जर्मनी और फ्रांस हैं।
- कंपनियों को अपने कर योग्य उत्सर्जन के एक निश्चित प्रतिशत तक ऑफसेट करने के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले अंतर्राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट का उपयोग करने की अनुमति भी दी जा सकती है।

अन्य देशों की स्थिति

- यूरोपीय संघ परिवहन को बाहर करता है।
- सिंगापुर उपयोगिता मूल्य वृद्धि से प्रभावित उपभोक्ताओं के लिए वाउचर प्रदान करता है।
- कैलिफोर्निया कार्बन परमिट की बिक्री से आय का उपयोग आंशिक रूप से इलेक्ट्रिक कारों की खरीद को सब्सिडी देने के लिए करता है। कुछ देश कार्बन टैक्स का उपयोग "उत्सर्जन गहन व्यापार " उद्यमों को छूट देने के लिए करते हैं, लेकिन आउटपुट-आधारित छूट ऐसा करने के बेहतर तरीके होंगे।
- ऑस्ट्रेलिया द्वारा 2012 में कर को स्थापित करने के दो साल बाद ही निरस्त कर दिया गया।

डीकार्बोनाइजेशन पर राजनीतिक दबावों का पता चला है जैसे

- ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने यूरोपीय संघ को लाखों उत्सर्जन परमिट बेचने के लिए प्रेरित किया, जिससे कार्बन की कीमतों में 10% की गिरावट आई।
- स्वीडन ने कुछ राजनीतिक बाधाओं के साथ-साथ कार्बन टैक्स को एक बड़े वित्तीय पैकेज के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया है जो अन्य करों को कम करता है और नए सामाजिक सुरक्षा जाल शामिल करता है।
- कुछ व्यक्तिगत उत्पादकों के नुकसान की उपस्थिति में भी, सामाजिक स्तर पर जीत के विचार का संचार करना महत्वपूर्ण है।
- अकेले चीन, यू.एस., भारत, रूस और जापान में पर्याप्त उच्च कार्बन टैक्स (60% से अधिक वैश्विक अपशिष्ट), पूरक कार्यों के साथ, वैश्विक प्रदूषण और वार्मिंग पर एक उल्लेखनीय प्रभाव है।